6

वैश्वीकरण

गत् शताब्दी के नौंवे दशक से विश्व बाजार में एक नये युग की शुरुआत हुई है । अब बाजार की व्यापकता एक क्षेत्र, राज्य और देश की सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया में हो गई। इसके पूर्व वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान में जो बाधाएँ थीं, उससे अब दुनिया का बाजार मुक्त हो गया है । वर्तमान स्थिति में छोटे से गाँव या शहर के बाजार में भी प्राय: वे सभी वस्तुएँ उपलब्ध होने लगी है । जिसके निर्माण का क्षेत्र उस देश से अलग दूसरे देशों में था । संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के अन्तर्गत पूरी दुनिया का बाजार एक-दूसरे के लिए मुक्त हो गया है ।

चित्र : 6.1 विभिन्न कंपनियों की कारें

व्यावहारिक रूप में यदि हम देखें तो हमें याद होगा कि कुछ वर्ष पूर्व हमारे देश की सड़कों पर केवल कुछ चुनिंदे नाम जैसे- मोटर साइकिल में राजदूत, एजडी तथा कार में फिएट तथा एम्बेस्डर ही चला करती थी । आज छोटे-से शहर की सड़कों पर भी नयी-नयी किस्म की गाड़ियाँ चलने लगी है । जिसका निर्माण बाहर के देशों में होता रहा है । इसी प्रकार किसी सामान्य दुकान पर भी

चले जाए तो उपभोक्ता के लिए वे सभी वस्तुएँ सर्वसुलभ हो गई है, जिसका निर्माण अन्य दूसरे देशों में होता है । अब छोटे–छोटे शहरों में भी बड़े–बड़े मॉल (Máll) खुल गए हैं, जहाँ उपभोक्ता के उपयोग की छोटी–से छोटी तथा बड़ी–से–बड़ी चीजें एक ही स्थान में उपलब्ध हो जाती है । सड़कों पर विभिन्न कंपनियों/देशों द्वारा निर्मित बड़ी छोटी गाड़ियाँ, दुकानों पर सामान्य उपयोग की समस्त वस्तुएँ, सामान्य उपयोग में आनेवाली मोबाइल एवं टेलीविजन आदि भी देश के बाजार में उपलब्ध होने लगी है । इस तरह के परिवर्तन जिसमें विश्व के विभिन्न देशों में बनी हुई वस्तुएँ सामान्य रूप से सभी जगह उपलब्ध होना, वैश्वीकरण का ही परिणाम है ।

मॉल
(Mall)

भारतीय उपभोक्ता बाजार में मॉल अपेक्षाकृत नयी अवधारणा है । वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के कारण देश के हर छोटे बड़े शहर में छोटे या बड़े पैमान पर ऐसा उपभोक्ता बाजार बनने लगा है जिसमें एक ही छत के नीचे उपभोक्ता के लिए हर छोटी एवं बड़ी चीजें मिलने लगी है । ऐसे ही बाजार को जिसमें एक छत के नीचे उपभोग की सारी छोटी एवं बड़ी वस्तुएँ उपलब्ध होती है उसे मॉल (Mall) कहते हैं । चूँकि मॉल के मालिक या व्यवस्थापक के द्वारा बड़े पैमाने पर वस्तुओं की खरीद की जाती है । इसलिए वे अपेक्षाकृत कम लागत लगने के कारण उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए, उनके ऊँची खरीद पर अनेक आकर्षक एवं लुभावने पुरस्कार देने की योजना बनाते हैं । उपभोक्ता बाजार में मॉल के प्रादुर्भाव से यद्यपि उपभोक्ताओं को एक ही छत के नीचे आकर्षक कीमत पर वस्तु मिलने से लाभ होता है । वहीं भारत जैसे देश में छोटे-छोटे व्यापारियों की बिक्री कम होने का खतरा उत्पन्न होने लगा है ।

चित्र : 6.2 मॉल

वैश्वीकरण क्या है ?

(What is Globalisation)

उदारीकरण और निजीकरण के साथ-साथ वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग अभी पिछले कुछ वर्षों से होने लगा है । वैश्वीकरण की अवधारणा में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू शामिल होते हैं । किन्तु यहाँ हम वैश्वीकरण की अवधारणा को उसके आर्थिक पहलू की दृष्टि से ही समझने का प्रयास करेंगे ।

वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूँजी और श्रम या मानवीय पूँजी का भी निर्बाध प्रवाह हो सके । वैश्वीकरण के अंतर्गत पूँजी, वस्तु तथा प्रौद्योगिकी का निर्बाध रूप से एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होता है । इसको स्पष्ट करते हुए **ब्रैंको मिलनोवीक** (Branko Milnovic) ने कहा है– "वैश्वीकरण का अर्थ पूँजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी एवं लोगों का विचार (Ideas) का स्वतंत्र प्रवाह होता है । कोई भी ऐसा वैश्वीकरण आंशिक ही माना

जाएगा जिसमें मानवीय संपदा के प्रवाह में रुकावट आये ।" (Globalisation means free movement of capital, goods, technology, ideas and people. Any globalisation that omits the last one is partial and not sustainable) अर्थात वैश्वीकरण के अन्तर्गत वस्तुओं के साथ-साथ पूँजी, तकनीक एवं सेवाओं का भी एक देश से दूसरे देश के बीच बिना किसी रुकावट के प्रवाह होता है । वैश्वीकरण के कारण ही विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं, पूँजी और प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान हो रहा है । दुनिया के देश एवं लोग एक-दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आये हैं ।

दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण; निजीकरण तथा उदारीकरण की नीतियों का परिणाम है-

निजीकरण (Privatisation) – निजीकरण का अभिप्राय, निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंध करना है । आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत भारत सरकार ने सन् 1991 से निजीकरण की नीति अपनायी ।

उदारीकरण (Liberalisation) – उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे– लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना है। आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत सन् 1991 से भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनायी ।

वैश्वीकरण (Globalisation)– निजीकरण और उदारीकरण की नीति की परिणति वैश्वीकरण के रूप में विश्व के सामने आयी है।

वैश्वीकरण के अंग (Components of globalisation)

वैश्वीकरण के पाँच मुख्य निम्नलिखित अंग है :–

1. व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी (Lesser the Obstacles of Business and Trade)– व्यापार अवरोधकों को कम करना ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं का बेरोकटोक आदान-प्रदान हो सके । इसका अभिप्राय यह हुआ कि विदेशी कंपनियाँ भारतीय बाजार में अपनी वस्तुएँ तथा सेवाएँ मुक्त रूप से बेच सकती है और इसी प्रकार भारतीय कंपनियाँ विदेशों में अपनी वस्तुएँ एवं सेवाएँ बेच सकती है ।

2. पूँजी का निर्बाध प्रवाह (Free Flow of Capital)– ऐसा वातावरण कायम करना जिससे विभिन्न देशों में पूँजी का प्रवाह स्वतंत्र रूप से हो सके । इसका अर्थ यह हुआ कि विदेशी पूँजीपति अब भारत में निवेश कर सकते हैं और भारतीय पूँजीपति विदेशों में निवेश कर सकते हैं।

3. प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह (Free Flow of Technology)– ऐसा वातावरण कायम करना कि प्रौद्योगिकी का निर्बाध या बिना बाधा के प्रवाह हो सके । इसका मतलब यह है कि हम बिना किसी प्रतिबंध के किसी भी देश से प्रौद्योगिकी आयात कर सकते हैं ।

4. श्रम का निर्बाध प्रवाह (Free Flow of Labour)– ऐसा वातावरण कायम करना कि विभिन्न देशों में श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके ।

5. पूँजी की पूर्ण परिवर्त्तनशीलता (Free Convertibility of Capital)– पूँजी की पूर्ण परिवर्त्तनशीलता भी वैश्वीकरण का आवश्यक अवयव है ।

यह देखने में आया है कि पूँजी, प्रौद्योगिकी, वस्तुओं तथा सेवाओं के क्षेत्र में दुनिया के विभिन्न देशों के बीच निर्बाध प्रवाह में काफी वृद्धि हुई है । परन्तु नागरिकों अर्थात श्रम आवागमन अभी उतना सुगम नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था । विकसित राष्ट्र श्रम के निर्बाध प्रवाह में बाधाएँ उत्पन्न कर रहे हैं ।

वैश्वीक गाँव
(Global Village)

वैश्वीकरण के प्रसार और प्रभाव के कारण अब सभी देशों में एक ऐसे आवासीय स्थान का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ आवास की सभी आधुनिकतम संसाधन उपलब्ध रहते हैं और उस आवासीय स्थान में विश्व के सभी देशों के व्यक्तियों को उनकी इच्छा से स्वतंत्र रूप में बसने की सुविधा होती है । ऐसा आवासीय स्थान जहाँ विभिन्न देशों, विभिन्न विचारों और विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के सभी लोगों को रहने की व्यवस्था की जाती है उसे ही हम वैश्वीक गाँव कहते हैं । भारत में भी मुंबई से कुछ दूर एक प्रमुख औद्योगिक समूह के द्वारा वैश्वीक गाँव का निर्माण किया गया है। यद्यपि वैश्वीक गाँव की यह कल्पना अब तक पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकी है ।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका (Role of Multinational Companies in globalisation)

बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ **वैश्वीकरण की** प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है ।

बहुराष्ट्रीय कंपनी
(Multinational Company)

बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है, जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है। जैसे–फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, नोकिया, इंफोसिस, टाटा मोटर्स आदि।

बहुराष्ट्रीय कंपनी की कार्य-प्रणाली

बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उत्पादन लागत में कमी करने एवं अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन जगहों या देशों में उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है, जहाँ उन्हें सस्ता श्रम, सस्ता

कच्चा माल एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत के उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की बड़ी कंपनी 'डाबर' अपनी वस्तु का उत्पादन सस्ती भूमि एवं श्रम की उपलब्धता के कारण नेपाल में भी करती है। **बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन विश्व-स्तर पर कर रही है**। इससे वे ज़्यादा लाभ कमाती है ।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एक अनोखी पद्धति, जिसे आउटसोर्सिंग (outsourcing) कहा जाता है, के द्वारा ये कंपनियाँ अपना कार्य करती है ।

बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ न तो सारा माल स्वयं पैदा करती हैं न ही एक जगह पर उत्पादन करती है । वे विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार का उत्पादन करती है । जैसे– औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी कंपनी अपने उत्पाद के लिए डिजाइन हो सकता है अमेरिका के किसी अनुसंधान व विकास केन्द्र से लें । इसके बाद इसी डिजाइन के आधार पर वह चीन में अवस्थित अपनी उत्पादन इकाई में पुर्जों के निर्माण का आर्डर देती है । इसका कारण है कि चीन में पुर्जों का सस्ता निर्माण संभव है । इसके बाद इन पुर्जों को जोड़ने का काम मैक्सिकों व पूर्वी यूरोप में किया जाता है । इसका कारण है कि मैक्सिकों और पूर्वी यूरोप, अमेरिका और यूरोप के बाजारों से निकट है, जिसके कारण लाभप्रद है । इसके बाद तैयार उत्पाद अन्तिम रूप में समूचे विश्व में बेचा जाता है । ग्राहक देखभाल सेवा के लिए **भारत स्थित कॉल सेंटरों** (call centres) का उपयोग किया जाता है । इसका कारण है कि भारत में काफी बड़ी संख्या में प्रशिक्षित, अंग्रेजी बोलने वाला सस्ता मानव शक्ति उपलब्ध है । इस प्रकार भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग स्थानों का चयन करके बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने लागत मूल्य को काफी हद तक कम करने में सफल होती है । इस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपना कारोबार विश्व-स्तर पर चलाती है और लाभ उठाती है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विश्व-भर के उत्पादन को एक-दूसरे से जोड़ना (Global Connection of Products)

बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कई प्रकार से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार करती है; जैसे–

चित्र : 6.3 यह पटना स्थित कॉल सेन्टर है

निवेश (Investment) - परिसंपत्तियों जैसे- भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं।

1. स्थानीय कंपनी को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। इसका उदाहरण है पारले समूह के 'थम्स अप' ब्रांड को कोका कोला (जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है) ने खरीद लिया।

विदेशी निवेश (Foreign Investment)- बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं । यह निवेश लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है ।

2. कभी-कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। इससे स्थानीय कंपनियों को एक तो नवीन प्रौद्योगिकी मिलता है, जिसे बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने साथ लाती है। दूसरा ज्यादा उत्पादन करने के लिए पूँजी मिलता है क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास काफी ज्यादा पूँजी होती है।

3. बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ माल के उत्पादन के लिए छोटे उत्पादकों का सहारा लेती है।

जैसे– वस्त्र, जूते, खेल के सामान, खिलौने आदि का उत्पादन बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए किया जाता है । बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ ये उत्पाद खरीद कर अपने ब्रांड नाम से दुनिया भर में बेचती है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ संयुक्त उपक्रम के माध्यम से या कंपनियों के विलय से या विभिन्न देशों के छोटे उत्पादकों से माल आपूर्ति ले करके अपना उत्पादन जाल फैलाती है । **इस तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा विश्व के दूर-दूर स्थानों पर फैला उत्पादन एक-दूसरे से संबंधित हो रहा है,** एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रहा है ।

वैश्वीकरण एवं बाजारों का एकीकरण (Globalisation and Integration of Market)

विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण का कार्य करते हैं । वैश्वीकरण के फलस्वरूप विदेशी व्यापार का दायरा बढ़ा है । पूर्व से ही विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य साधन रहा है । व्यापार करने के लिए ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आयी । ऐसे कई उदाहरण इतिहास में हम पढ़ते हैं । विदेश व्यापार, उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर निकलकर दूसरे देश के बाजारों में पहुँचने एवं विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करता है । यदि विदेशी व्यापार पर कोई नियंत्रण न हो तो माल एक देश से दूसरे देश में सुगमता से आ सकेगा । जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं का बाजार में विकल्प बढ़ जाते हैं और विभिन्न देशों के बाजारों में वस्तुओं के मूल्य लगभग समान हो जाते हैं । वैश्वीकरण के फलस्वरूप विदेशी व्यापार पर नियंत्रण में ढीलापन आया है ।

इस प्रकार विदेशी व्यापार दुनिया के देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण का कार्य करता है ।

वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक (Factors Responsible for Globalisation)

वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने वाले दो मुख्य कारक है । उनकी चर्चा नीचे की गई है।

1. प्रौद्योगिकी में प्रगति – प्रौद्योगिकी के मामले में हमने काफी विकास किया है ।

प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। आज हम ऐसे प्रौद्योगिकी के युग में जी रहे हैं जब समय एवं स्थान की दूरियाँ सिमट गई हैं और दुनिया एक वैश्विक गाँव बन गई है। यातायात व दूरसंचार के क्षेत्र में हुई प्रौद्योगिकी प्रगति ने भौगोलिक दूरियों को पार करने में न सिर्फ समय कम कर दिया है, बल्कि खर्च भी घटा दिया है।

परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। अब माल ढोने के लिए कंटेनरो का उपयोग किया जाता है। जिससें माल के ढुलाई-लागत में कमी आयी है। इसी प्रकार रेल एवं हवाई यातायात की लागत में गिरावट आयी है। जिससे वायुमार्ग से अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है।

चित्र : 6.4 वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को काफी तेज किया है। दूरसंचार सुविधाओं (टेलीफोन, मोबाईल फोन, फैक्स) के द्वारा हम दुनिया के किसी

भी कोने से तुरंत संपर्क बना सकते हैं । इसमें संचार उपग्रहों ने काफी मदद किया है ।

आज कम्प्यूटर का प्रवेश घर-घर में हो रहा है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कम्प्यूटर का प्रवेश हो गया है । आज इंटरनेट की दुनिया है जहाँ हम जो चाहते हैं, घर के कोने में बैठे-बैठे दुनिया की सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं । इसके द्वारा हम तुरंत इलेक्ट्रॉनिक डाक (ई-मेल) भेज सकते हैं और कम मूल्य पर दुनिया भर में बात कर सकते हैं । सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मददगार सिद्ध हो रहा है । इसे हम निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं – मान लीजिए न्यूयार्क का प्रकाशक जो पत्रिका या पुस्तक प्रकाशित करना चाहता है । वह लागत कम करने के लिए पत्रिका के पाठ्य-विषय, योजना एवं डिजाइन को इंटरनेट एवं दूरसंचार के माध्यम से अपने मुंबई कार्यालय को भेज देता है । मुंबई कार्यालय उसे मुंबई में ही न्यूयार्क से भेजे गए डिजाइन के आधार पर प्रकाशित करता है । छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायुमार्ग से न्यूयार्क भेजा जाता है । पत्रिका के छपाई एवं डिजाइनिंग के लिए पैसे का भुगतान इंटरनेट के द्वारा न्यूयार्क के एक बैंक से मुंबई के एक बैंक को तत्काल (ई-बैंकिंग द्वारा) कर दिया जाता है।

इस तरह हम देखते हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों को नजदीक लाकर वैश्वीकरण की प्रक्रिया को काफी तेज किया है ।

2. विदेश-व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण– अपनी योजना के शुरू के वर्षों में भारत ने अपने यहाँ विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था । यह नीति घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए थी।

सन् 1991 से उदारीकृत व्यापार नीति प्रारंभ की गई, विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधकों (जैसे आयात पर कर आदि) को काफी हद तक हटा दिया गया । दूसरे शब्दों में अब आयात-निर्यात बेरोक-टोक किया

> **व्यापार अवरोधक–** इसे अवरोधक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है । सरकार व्यापार अवरोध का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने एवं कौन-सी वस्तु देश में कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए करती है।

जाने लगा था। विदेशी कंपनियाँ यहाँ पर अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती है। अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण का नाम दिया गया है ।

विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश के उदारीकरण की इस नीति से भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है ।

विश्व व्यापार संगठन

(World Trade Organisation- W.T.O.)

विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.) एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है इस संगठन की स्थापना जनवरी 1995 में की गई थी । भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है । वर्तमान में 149 देश विश्व व्यापार संगठन (2006) के सदस्य हैं । इसका मुख्यालय जेनेवा में है । विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और देखता है कि इन नियमों का पालन हो । विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है । परन्तु विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बना रखा है । दूसरी ओर विकासशील देशों पर दवाब डालकर उन्हें व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए विवश किया जाता है ।

भारत में वैश्वीकरण क्यों ?

(Globalisation in India-Why ?)

विकास की वर्तमान स्थिति में भारत के उद्योग एवं व्यापार को नई प्रौद्योगिकी और ज्ञान की अतिशय आवश्यकता है । इसके साथ ही जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत एक बड़ा देश है, जिसके कारण उत्पादन के सस्ते साधनों की उपलब्धता के कारण यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है । विश्व का बड़ा उपभोक्ता बाजार होने के कारण दुनिया के सभी देशों की निगाह भारत पर है । ऐसी स्थिति में देश में आधुनिक तकनीकी ज्ञान एवं पूँजी को आकर्षित करने के लिए तथा विश्व बाजार में मानव पूँजी और उत्पादित वस्तु को भेजने में वैश्वीकरण का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ जाता है ।

वैश्वीकरण के समर्थक **भारत में वैश्वीकरण** के पक्ष में निम्नलिखित तर्क देते हैं–

1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन (Increase in Direct Foreign Investment)– वैश्वीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहित होगा । जिससे भारत जैसे विकासशील देश अपने विकास के लिए पूँजी प्राप्त कर सकेगा ।

2. प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि (Increase in Competitive Power)– वैश्वीकरण की नीति के फलस्वरूप भारत जैसे विकासशील देशों की प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था का त्वरित विकास हो सकेगा ।

वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क :

1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन
2. प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि
3. नई-प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक
4. अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति
5. नये बाजार तक पहुँच
6. उत्पादन तथा उत्पादिता के स्तर को उन्नत करना
7. बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार
8. मानवीय पूँजी की क्षमता का विकास

3. नई-प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक (Facilitates New Technology) – वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा तैयार की गई नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायता प्रदान करता है ।

4. अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति (Availability of High Quality Consumer Goods)– वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों को अच्छी-अच्छी गुणवत्ता की उपभोग वस्तुओं को सापेक्षतः कम कीमत पर प्राप्त करने के योग्य बनाता है ।

5. नये बाजार तक पहुँच (Availability of New Market)– वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया के बाजारों तक पहुँच का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा।

6. उत्पादन के स्तर को उन्नत करना (Improvement in the Quality of Product)– वैश्वीकरण के द्वारा उन्नत मशीन तथा तकनीक के प्रयोग से उत्पादन के स्तर को उठाया जा सकता है ।

7. बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार (Banking and Financial Reform)–

वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के अन्य देशों के संपर्क में आने से बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र की कुशलता में सुधार होगा ।

6. मानवीय पूँजी की क्षमता का विकास (Improvement in the Efficiency of Human Capital)– शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण वैश्वीकरण के प्रमुख घटक हैं । इससे मानवीय विकास को बढ़ावा मिलता है ।

भारत सहित विश्व के कई देशों में वैश्वीकरण के गुण-दोष को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है । भारत में भी एक वर्ग के आर्थिक और सामाजिक चिंतकों का मानना है कि वैश्वीकरण यहाँ के अर्थव्यवस्था के औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र के लिए घातक होगा । यद्यपि उनके द्वारा दिये गये तर्कों में कुछ तथ्य है । उदाहरण के लिए पूँजी एवं श्रम बाजार में इससे अधिक नुकसान होने की संभावना व्यक्त की जाती है । इक्कीसवीं शताब्दी का विश्व पिछले कुछ वर्षों से एक अलग युग में प्रवेश कर गया है । जहाँ चीन एवं रूस में भी बड़े पैमाने पर विदेशी पूँजी और श्रम के लिए पूर्व के अवरोधों से मुक्ति करा दी गई है । ऐसी परिस्थिति में अब भारत के लिए भी वैश्वीकरण के महत्त्व को नकारना मुश्किल हो गया है । सच तो यह है कि भारत की औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए वैश्वीकरण की नीति अनिवार्य दिखती है ।

वैश्वीकरण-ऐतिहासिक परिवेश में (1991 के पूर्व का वैश्वीकरण)

वैश्वीकरण की प्रक्रिया विश्व के लिए नई नहीं है । वर्ष 1870 से 1914 के दौरान भी ऐसा ही एक दौर देखने में आया था । यद्यपि वैश्वीकरण के आज के चरण एवं पहले के चरण में अनेक समानताएँ हैं । उन्नसवीं सदी के अंत में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था आज की तरह ही संगठित हुई थी । एक बात में वैश्वीकरण के ये दोनों चरण एक-दूसरे से भिन्न है और वह है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास अथवा देशांतरण । पिछले चरण (1870 ई० से 1914 ई०) में जहाँ बड़े पैमाने पर श्रमिकों का बिना बाधा का प्रवाह हुआ वहीं इस चरण में एक तो प्रवाह की गति धीमी पड़ गई है और इसका स्वरूप भी बदल गया है । वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक भी दोनों दौरों में लगभग एक समान थे । उन दिनों दो देशों के बीच वस्तु, पूँजी और श्रम के आवागमन पर लगभग कोई रोक नहीं थी । भाप के जहाजों, रेलों

और तारों (Telegram) के जरिए यातायात और संचार में भारी बदलाव आए थे । उद्योगों में नई-नई प्रबंध और उत्पादन तकनीक अपनायी जा रही थी । आज के अमेरिकी प्रभुत्व के समान उन दिनों ब्रिटेन का दुनिया पर राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व बना हुआ था तथा पाउंड स्टरलिंग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की भूमिका निभा रहा था।

बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव

वैश्वीकरण के कारण बिहार का आर्थिक परिवेश भी बदलता जा रहा है । आर्थिक विकास के लिए अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी अधिक पूँजी निवेश की आवश्यकता है । पूँजी के संबंध में यह कहा जाता है कि जिस तरह पानी की तरलता नीची भूमि में पानी को आकर्षित करती है उसी तरह पूँजी का निवेश वहाँ होता है जहाँ आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण स्वस्थ हो तथा पूँजी से उत्पाद-लाभ अधिक हो । आर्थिक स्वस्थता से हमारा तात्पर्य उद्योग के लिए बिजली, पानी, सड़क जैसे यातायात की सुविधाओं का होना आवश्यक है । उसी तरह सामाजिक स्वास्थ्य के लिए राज्य में अमन चैन का होना आवश्यक है, जिससे निवेशक अधिक सुरक्षा कवच के अंदर अपना पूँजी निवेश कर सके । यद्यपि बिहार में शक्ति के साधन के रूप में बिजली पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी सड़क आदि का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है तथा कानून एवं व्यवस्था में अपक्षाकृत सुधार लाने के प्रयास किये जा रहे हैं । यह वैश्वीकरण की ही देन है कि सरकार एवं नागरिकों द्वारा राज्य में आधारिक संरचना (Infrastructure) का विकास हो रहा है, जिससे राज्य की प्रगति तीव्र हो सके । भारत के पूर्व राष्ट्रपति ए० पी० जे० अबुल कलाम ने किसी एक संदर्भ में यह कहा था "देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है ।"

वैश्वीकरण के वर्तमान युग में उपभोग एवं उत्पादन के क्षेत्र में पूरी दुनिया एक देश हो गया है और इस कारण वैश्वीकरण के सुखद परिणाम बिहार राज्य में भी दिखायी पड़ने लगे हैं । प्रगति के वर्तमान स्थिति में और अधिक मजबूती लाना होगा, तभी हमें वैश्वीकरण का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है ।

वैश्वीकरण का बिहार के जनजीवन पर न केवल सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं बल्कि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है जिसे हम निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

देश की तरह बिहार के आर्थिक व्यवस्था पर वैश्वीकरण का कुछ सकारात्मक प्रभाव (Positive Impact) पड़ा है जो निम्नलिखित है :-

1. कृषि उत्पादन में वृद्धि (Increase in agriculture production)– वैश्वीकरण के बाद बिहार के कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।

देश की तरह बिहार की कृषि भी मॉनसून पर अतिशय आश्रित है यही कारण है कि इस वर्ष 2009 में आशा से कम वर्षों होने के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति पैदा हो गयी है । यह वैश्वीकरण का ही प्रभाव है कि आज कृषि उत्पाद के इस गिरावट की स्थिति में भी सरकार यह कहने में सक्षम है कि लोगों के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता की भरपाई की जा सकेगी ।

2. निर्यातों में वृद्धि (Increase in exports)– वैश्वीकरण के फलस्वरूप बिहार से किये गये निर्यातों में वृद्धि हुई है । इन निर्यातों में कुछ खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों का निर्यात, कुटीर तथा लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात तथा फलों का निर्यात शामिल है फलों के निर्यात के अंतर्गत बिहार लीची, आम तथा मखाना के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है ।

बिहार में वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव

1. कृषि उत्पादन में वृद्धि (Increase in agriculture production)
2. निर्यातों में वृद्धि (Increase in exports)
3. विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति (Availability of foreign direct investment)
4. शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि (Increase in net state domestic product and per capita net state domestic product)
5. विश्वस्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता (Availability of International Consumer Goods)
6. रोजगार के अवसरों में वृद्धि (Increase in Employment oppurtunities)
7. बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियों का आगमन (Establistment of Banking and Insurance Company)

3. विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति (Availability of foreign direct investment)– वैश्वीकरण के फलस्वरूप बिहार में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग भी हुआ है और विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के लिए काफी दिलचस्पी दिखाई गई है। इससे भविष्य में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग में काफी वृद्धि की आशा की जा सकती है। बिजली की कमी के कारण प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग अभी कम है किन्तु भविष्य में बढ़ने की संभावना है।

4. शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि (Increase in net state domestic product and per capita net state domestic product)– वैश्वीकरण के फलस्वरूप चालू मूल्यों पर बिहार के शुद्ध घरेलू उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है। दूसरे शब्दों में इस अवधि में राज्य की कुल आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है।

5. विश्वस्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता (Availability of World-class Consumer Goods)– वैश्वीकरण के कारण बिहार के बाजारों में विश्वस्तरीय उपभोक्ता वस्तुएँ उपलब्ध हो गयी है। विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मोबाईल फोन, जूते, रेडिमेड वस्त्र, खाद्य-पदार्थ, कारें एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ आदि अब बिहार के बाजारों में भी उपलब्ध है।

6. रोजगार के अवसरों में वृद्धि (Increase in Employment opportunities)– वैश्वीकरण के फलस्वरूप रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त लोगों के लिए विदेशों तथा देश के अन्य भागों में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हुए हैं। वैश्वीकरण का ही प्रभाव है कि बिहार के बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं इंगलैंड में बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर इंजीनियर नौकरी कर रहे हैं।

7. बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियों का आगमन (Establishment of Banking and Insurance Company)– वैश्वीकरण का ही प्रभाव है कि बिहार में बहुराष्ट्रीय बैंकों जैसे HSBC बैंक आदि का आगमन हुआ।

बिहार में बहुराष्ट्रीय बीमा कंपनियाँ, भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त कंपनी के

रूप में बाजार में उतर रही है । जैसे– बजाज एलियांज, बिरला सनलाइफ, टाटा ए० आई० जी०, अवीवा आदि ।

वैश्वीकरण के कारण बिहार के बाजार में भी बड़े पैमाने पर विश्व बाजार का श्रेष्ठतम उत्पाद उपलब्ध हो गया है । तकनीक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी विश्व की उन्नत देशों की शैक्षणिक संस्थाएँ अपना केन्द्र बिहार में खोलने को इच्छुक है । बिहार के प्रशिक्षित तकनीकी विशेषज्ञों की माँग विदेश में बढ़ गई है और शिक्षित एवं प्रशिक्षित लोगों के लिए रोजगार के नये अवसर आने लगे हैं । विगत वर्षों में बिहार के आधारभूत संरचना (Infrastructure) के विकास के कारण विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में बिहार आने लगे हैं और विश्व मुद्रा बाजार से बिहार में पूँजी निवेश की संभावना बढ़ती जा रही है ।

नकारात्मक प्रभाव (Negative Impact)

बिहार के आर्थिक जीवन पर वैश्वीकरण का जो नकारात्मक प्रभाव (Negative Impact) पड़ा है उसे हम मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं :-

1. कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा (Neglect of agriculture and agro based industries)– बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है । यहाँ बड़े पैमाने पर उद्योग-धंधे काफी कम है । राज्य में कृषि पर किया गया निवेश संतोषजनक नहीं है । यहाँ कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावना काफी है । लेकिन, इन उद्योगों में वैश्वीकरण के पश्चात् जितना निवेश होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है ।

2. कुटीर एवं लघु उद्योग पर विपरीत प्रभाव (Adverse effect on cottage and small scale industry)– बिहार में बड़े पैमाने के उद्योग-धंधे कम हैं । यहाँ कुटीर एवं लघु उद्योग ज्यादा हैं। वैश्वीकरण के कारण छोटे पैमाने के उद्योगों जैसे कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है क्योंकि उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं का सामना करना पड़ता है जो क्वालिटी में इनसे अच्छी एवं सस्ती होती हैं । जैसे– चीन द्वारा निर्मित खिलौने से हमारा बाजार पट गया है। चीनी खिलौनों ने हमारे कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग द्वारा निर्मित खिलौनों को दर किनार कर दिया है क्योंकि चीनी खिलौने

आकर्षक एवं सस्ते हैं ।

3. रोजगार पर विपरीत प्रभाव (Adverse effect on employment)– चूँकि बिहार में छोटे पैमाने के उद्योग धंधे ज्यादा है जैसे कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग आदि । बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं के आने से इन उद्योगों की बहुत सारी इकाईयाँ बंद हो गई । जिसके कारण बहुत सारे श्रमिक बेरोजगार हो गये । बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता श्रम-लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। वे श्रमिकों को स्थायी रोजगार की जगह अब अस्थायी रोजगार देते हैं । इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है ।

बिहार में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव

1. कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा
2. कुटीर एवं लघु उद्योगों पर विपरीत प्रभाव
3. रोजगार पर विपरीत प्रभाव
4. आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश

4. आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश (Low investment due to poor growth of infrastructure)– बिहार में पूँजी निवेश उतना नहीं हुआ है जितना वैश्वीकरण के फलस्वरूप देश के अन्य राज्यों में हुआ है। इसका कारण है कि बिहार में आधारभूत संरचना की कमी है। यहाँ सड़क, बिजली, विश्वस्तरीय होटल एवं हवाई अड्डा की कमी है।

बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, परन्तु इस क्षेत्र में और अधिक कदम उठाने की जरूरत है।

इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के सकारात्मक अथवा लाभकारी प्रभाव इनके नकारात्मक प्रभावों की तुलना में अधिक वजन रखते हैं । स्पष्टत: वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर से नहीं बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है । वास्तव में वैश्वीकरण एक उभरती हुई एवं सशक्त अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता है जिसकी अपनी एक गति है । बिहार में समय के साथ यह गति सशक्त होती चली जायेगी । इसके लिए हमें वैश्वीकरण के लाभों को अधिकतम एवं इसके जोखिमों को न्यूनतम बनाने का

प्रयास करते रहना होगा ।

सन् 1991 का आर्थिक सुधार (Economic Reforms Since 1991)

1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि उसके धारक क्षमता से अधिक माना जाने लगा । आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की संवृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था । पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया **विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार** पंद्रह दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी । उस समय स्थिति ऐसी आ गयी थी कि भारत को 49 क्विंटल सोना बैंक ऑफ इंगलैंड में बंधक रखना पड़ा था । 1990-91 के खाड़ी युद्ध ने संकट को और गहरा बना दिया। इन सभी कारणों से सरकार ने सन् 1991 में कुछ नई नीतियों को अपनाया जिसे **नई आर्थिक नीति** कहा जाता है । इस नई आर्थिक नीति में व्यापक **आर्थिक सुधारों** को सम्मिलित किया गया ।

आर्थिक सुधारों का अर्थ (Meaning of Economic Reforms)

भारत में आर्थिक सुधारों का मतलब उन नीतियों से है जिनका प्रारंभ 1991 से अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता एवं प्रतियोगिता की शक्ति के स्तरों में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से किया गया है ।

ये आर्थिक सुधार उदारीकरण (Liberalisation), निजीकरण (Privatisation) तथा वैश्वीकरण (Globalisation) की नीतियों पर आधारित है । अत: इन्हें हम LPG नीति भी कहते हैं । यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि आर्थिक सुधारों को हम नई आर्थिक नीति (New Economic Policy) के नाम से भी पुकारते हैं ।

LPG की व्याख्या

L= Liberalisation

P= Privatisation

G= Globalisation

आर्थिक सुधारों अथवा नई आर्थिक नीति के उद्देश्य

(Objectives of economic reforms or new economic policy)

आर्थिक सुधारों अथवा नई आर्थिक नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. उत्पादन इकाइयों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता स्तर में सुधार लाना ।
2. उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना ।
3. भूतकाल की तुलना में विदेशी विनियोग (Foreign Investment) एवं तकनीक का अधिक-से-अधिक उपयोग करना ।
4. आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना ।
5. आर्थिक विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधनों का प्रयोग करना ।
6. वित्तीय क्षेत्र (Financial Sector) में सुधार लाना तथा इसे आधुनिक बनाना ताकि यह अर्थव्यवस्था की जरूरतों को प्रभावशाली ढंग से पूरा कर सके ।
7. सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य-संपादन (Performance) में सुधार लाना तथा उसके क्षेत्र को अधिक युक्तिसंगत बनाना ।

आर्थिक सुधारों या नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताएँ (Main Features of Economic Reforms or New Economic Policy)

नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताएँ अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण करना है ।

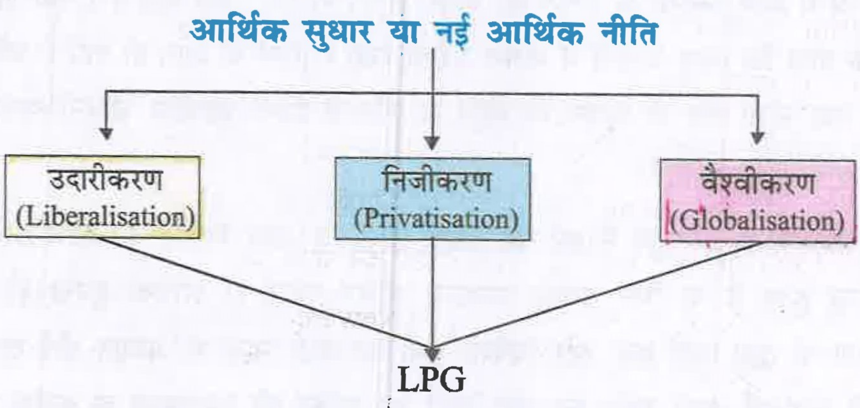

उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की चर्चा इस अध्याय में पहले की जा चुकी है ।

वैश्वीकरण एवं आम आदमी
(Globalisation and Common Man)

देश में सामान्यतः ऐसे लोगों की संख्या अधिकतम होती है जो उपभोग की न्यूनतम सुविधाओं (Minimum Comfort) से या तो वंचित रहते हैं या उस सीमा-रेखा से थोड़ा ऊपर होते हैं। सामान्यतः आम आदमी (Common Man) समाज के ऐसे वर्ग-समूह को कहते हैं जो मध्यम अथवा निम्न श्रेणी के लोग होते हैं जो सामान्य उपभोग की सुविधाओं से वंचित होते हैं। जो किसी तरह अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। भारत में वर्तमान के वर्ष (2009-10) में करीब-करीब 85 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जिनकी आय कम है और जिन्हें जीवन-यापन की सामान्य सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे वर्ग-समूह को ही हम आम आदमी कहते हैं। NCAER (National Council of Applied Economic Research) ने 2006 के प्रकाशित **द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास** में आय के आधार पर यह बतलाने की कोशिश की है कि भारतीय सामाजिक संरचना में आम आदमी की कितनी भागीदारी है।

देश की पूरी जनसंख्या का लगभग 85% लोग ऐसे हैं जो जीवनयापन की सामान्य सुविधाओं से वंचित है या जिन्हें जीवन की न्यूनतम सुविधाएँ मुश्किल से उपलब्ध होती हैं। भारत के आम आदमी जिसकी संख्या इतनी बड़ी है और जनतांत्रिक व्यवस्था में इनकी भागीदारी भी बहुत बढ़ जाती है। यही कारण है कि भारतीय जनतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के समय हर पार्टी के घोषणा-पत्र में आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के वादे किये जाते हैं। यहाँ यह कह देना आवश्यक होगा कि आम आदमी में केवल गरीबी रेखा से निचे के लोग ही नहीं है बल्कि गरीबी रेखा के उस सीमा क्षेत्र के ऊपर भी बहुत से लोग है जिन्हें सामान्य जीवनोपयोगी सुविधाएँ मुश्किल से उपलब्ध होती है।

वैश्वीकरण के इस युग में हमें यह देखना होगा कि आम आदमी को वैश्वीकरण से क्या लाभ प्राप्त हुआ है या फिर उनका सामान्य जीवन पहले से अधिक दुर्बल हो गया है। वैश्वीकरण के द्वारा जहाँ एक ओर विदेशी पूँजी का बड़ी मात्रा में आयात होने लगा है और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अपने उद्योग का केन्द्र सस्ते श्रम शक्ति की उपलब्धता के कारण भारत जैसे देश में लगाने लगे हैं। पूँजी और उद्योग के क्षेत्र में विदेशी पूँजी के लगने से लोगों को अधिक

रोजगार मिलने की संभावना व्यक्त की जाती रही है । मूल रूप से आम आदमी पर वैश्वीकरण का निम्नलिखित अच्छा प्रभाव पड़ा है–

1. उपयोग के आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता– वैश्वीकरण के कारण दुनिया के सभी देशों के उच्चतम उत्पादन लोगों को उपयोग के लिए उपलब्ध हो गया है । उदाहरण के लिए पहले जहाँ आम आदमी रेडियो से मनोरंजन प्राप्त करता था । अब उनके लिए विभिन्न कंपनियों की रंगीन टेलीविजन जैसी चीजों की उपलब्धता हो गई है ।

आम आदमी पर वैश्वीकरण का अच्छा प्रभाव
1. उपयोग के आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता
2. रोजगार की बढ़ी हुई संभावना
3. आधुनिकतम तकनीक की उपलब्धता

2. रोजगार की बढ़ी हुई संभावना– वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक प्रसार होने के कारण रोजगार के नए-नए क्षेत्र खुल गए हैं । जिससे कुशल श्रमिकों के लिए अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो गए हैं ।

3. आधुनिकतम तकनीक की उपलब्धता– वैश्वीकरण के कारण विश्व के विकसित देशों के आधुनिकतम तकनीक अन्य विकासशील देशों में आसानी से उपलब्ध होने लगा है । जिससे आम लोगों के लिए आधुनिकतम तकनीक के उपयोग का दरवाजा खुल गया है ।

सच कहा जाए तो, भारत जैसे विकासशील देश में आम लोगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव ही पड़ा । वैश्वीकरण से आम लोगों पर निम्नलिखित बुरा प्रभाव पड़ा है–

1. सामान्यतः कम कुशल लोगों में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका – वैश्वीकरण के कारण आधुनिक संयंत्रों से मशीनी उत्पादन को बढ़ावा मिला है, जिसके कारण समाज के अधिकतम श्रम-शक्ति जो अर्धकुशल (Semiskilled) या अकुशल (unskilled) हैं । ऐसे लोगों में बेरोजगारी के बढ़ने की संभावना हो गई है ।

2. उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता– वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से देश के अंदर के उत्पादकों को विदेशी ऐसी वस्तुओं से प्रतियोगिता करनी पड़ रही है जो उन्नत तकनीक के कारण उच्च स्तर के होते हैं तथा अत्याधुनिक पैकिंग के कारण आकर्षक दिखते हैं ।

3. श्रम-संगठनों पर बुरा प्रभाव– श्रमिक संगठनों के द्वारा आम मजदूरों की न्यूनतम माँगों को संगठित रूप से माँग की जाती है जिससे श्रमिकों को सामान्य वेतन एवं सुविधाएँ उपलब्ध होने लगती है । अब वैश्वीकरण के कारण श्रम कानूनों में लचीलापन आया है जिससे श्रमिक संगठन भी कमजोर हो गया है इससे आम श्रमिकों की उचित सेवा-सुविधाओं को मिलने में अधिक कठिनाई आने लगी है ।

आम आदमी पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव

1. बेरोजगारी बढ़ने की आशंका
2. उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता
3. श्रम-संगठनों पर बुरा प्रभाव
4. मध्यम एवं छोटे उत्पादकों की कठिनाई
5. कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का संकट

4. मध्यम एवं छोटे उत्पादकों की कठिनाई– वैश्वीकरण के कारण मध्यम एवं छोटे उत्पादकों के लिए अपने उत्पादन को सक्षम बनाए रखने में अनेक कठिनाइयाँ होने लगी हैं प्रकृति का यह एक सामान्य नियम है कि पानी में बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियों को खा जाती है। उसी तरह वैश्वीकरण के कारण जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ देश में आने लगी है उससे मध्यम और छोटे उद्योग और व्यवसाय के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है ।

5. कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का संकट– वैश्वीकरण के कारण अब देश और विदेश के बड़े-बड़े पूँजीपति फार्म हाऊस बनाने लगे हैं जिसमें कृषि के क्षेत्र में भी अधिक पूँजी निवेश के द्वारा कम श्रम-शक्ति से ही अधिक उत्पादन प्राप्त करने लगे हैं । इस स्थिति में गाँव के मध्यम एवं छोटे श्रेणी के किसानों के लिए अनेक प्रकार का संकट उत्पन्न हो गया हैं ।

वैश्वीकरण का आम लोगों पर कुछ अनुकूल एवं अधिक विपरीत प्रभावों को देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि वैश्वीकरण से आम लोगों को लाभ से अधिक हानि होने की संभावना है । यह सत्य है कि वैश्वीकरण से पूँजी, उत्पाद और आय में वृद्धि होगी । किन्तु वृद्धि का यह लाभ समाज के मुट्ठी-भर धनी एवं उच्च शिक्षा प्राप्त लोग ही प्राप्त कर सकेंगे । वैश्वीकरण की स्थिति में ऊँची आय के अमीर व्यक्तियों की आय बढ़ती चली जाएगी और 85 प्रतिशत की सर्वाधिक संख्या में आम लोगों का जीवन कठिन हो जाने की संभावना है । अतः विकास की व्यूह-रचना समावेशी होनी चाहिए ।

देश का आम आदमी बहुत मुश्किल से अपने जीवनयापन की न्यूनतम सुविधा प्राप्त कर पाता है । ऐसे लोगों के लिए वैश्वीकरण के कारण अन्य देशों में उत्पादित उच्च मूल्य के वस्तुओं

का उपभोग करना कठिन होता है । देश का आम आदमी गरीबी, भुखमरी आदि के शिकार होते रहते हैं इस कारण उन्हें वैश्वीकरण का कोई लाभ नहीं मिल पाता है । यह बात अलग है कि अर्द्धविकसित एवं विकासशील देशों में सस्ते श्रम-शक्ति की उपलब्धता के कारण नये-नये उद्योग की स्थापना और विकास की जाती है जिससे देश के सामान्य कुशलता प्राप्त श्रमिकों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती है ।

आम लोगों पर वैश्वीकरण के प्रभावों को देखने से यह पता चलता है कि तत्काल में भारत के आम लोगों को वैश्वीकरण से पर्याप्त लाभ मिलने की संभावना कम है । 21वीं शताब्दी के भारत के विकास के संबंध में जो संभावित स्थिति बनती है उसमें भारत एक सम्पन्न विकसित देश होने के कगार पर है । ऐसी स्थिति में वर्तमान में यदि न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली एवं सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास (Inclusive Growth) के आधार पर समाज के सभी वर्गों तथा सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास किया जाए तभी वैश्वीकरण का तात्कालिक लाभ आम लोगों को प्राप्त हो सकेगा । विकास कि गति में वृद्धि के साथ आम लोगों को मिलने वाली सामान्य सुविधाओं में वृद्धि होने की संभावना है जिससे हम कह सकते हैं कि यदि विकास की गति में तीव्रता आयी तो आम लोगों को वैश्वीकरण से पर्याप्त लाभ हो सकेगा । इस लाभ को प्राप्त करने के लिए देश में ईमानदारी से सभी वर्गों के उत्थान के लिए योजनात्मक कदम उठाना होगा जिसे हम समावेशी विकास (Inclusive Growth) के रूप में व्यक्त करते हैं ।

सारांश

- **वैश्वीकरण**– वेश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है । ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूँजी ओर श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके ।
- **वैश्वीकरण के पाँच मुख्य अंग हैं**– (i) व्यापार अवरोधकों को कम करना। (ii) ऐसी परिस्थिति बनाना जिससे विभिन्न देशों में पूँजी का प्रवाह स्वतंत्र रूप से हो सके। (iii) ऐसा वातावरण कायम करना कि प्रौद्योगिक का निर्बाध प्रवाह हो सके । (iv) ऐसा वातावरण कायम करना कि श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके । (v) पूँजी की मुक्त परिवर्तनशीलता ।

- बहुराष्ट्रीय कंपनी– वह है, जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है ।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन विश्व-स्तर पर करके एवं विश्व भर के उत्पादन को एक-दूसरे से जोड़कर, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है ।
- विदेश व्यापार, विश्व के देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण का कार्य करते हैं ।
- वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक निम्न हैं– (i) प्रौद्योगिकी में प्रगति । (ii) विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण ।
- **विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.)**– यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और देखता है कि इन नियमों का पालन हो ।
- भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क है– (i) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन (ii) प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि, (iii) नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक, (iv) अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति, (v) नये बाजार तक पहुँचना, (vi) उत्पादन तथा उत्पादिता के स्तर की उन्नत करना, (vii) बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार, (viii) मानवीय पूँजी की क्षमता का विकास ।
- **वैश्वीकरण का बिहार पर प्रभाव**– इसका सकारात्मक एवं नकारात्मक दो तरह के प्रभाव बिहार पर पड़े हैं–

सकारात्मक प्रभाव– (i) कृषि उत्पादन में वृद्धि, (ii) निर्यातों में वृद्धि, (iii) विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति, (iv) शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन एवं प्रति-व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि (v) निर्धनता में कमी, (vi) विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता, (vii) रोजगार के अवसरों में वृद्धि, (viii) बहुराष्ट्रीय बैंकों एवं बीमा कंपनियों का आगमन ।

नकारात्मक प्रभाव– (i) कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा, (ii) कुटीर एवं लघु उद्योगों पर विपरीत प्रभाव, (iii) रोजगार पर विपरीत प्रभाव, (iv) आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश ।

- **भारत में सन् 1991 का आर्थिक सुधार**–उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीतियों पर आधारित है। इसलिए इन्हें LPG नीति भी कहते हैं। आर्थिक सुधारों को हम नई आर्थिक नीति के नाम से भी जानते हैं।
- **उदारीकरण**– इसका अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे परमिट, लाइसेंस, कोटा आदि से अर्थव्यवस्था की मुक्ति।
- **निजीकरण**– निजीकरण से अभिप्रांय है, निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंध करना। निजी क्षेत्र के विकास पर प्रतिबंध हटाना।
- **वैश्वीकरण एवं आम आदमी** – वैश्वीकरण के आम लोगों पर कुछ अनुकूल एवं अधिक विपरीत प्रभाव पड़ा है।

प्रश्नावली

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Question)

I. सही विकल्प चुनें।

1. नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया ?

(क) उदारीकरण (ख) निजीकरण (ग) वैश्वीकरण (घ) उपर्युक्त सभी

2. वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं ?

(क) एक (ख) दो (ग) पाँच (घ) चार

3. इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है ?

(क) फोर्ड मोटर्स (ख) सैमसंग (ग) कोका-कोला (घ) इनमें से सभी

4. वैश्वीकरण का अर्थ है –

(क) विदेशी पूँजी एवं विनियोग पर रोक

(ख) व्यापार, पूँजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय

(ग) सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना

(घ) इनमें कोई नहीं

5. पारले समूह के 'थम्स अप' ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया?

(क) कोका कोला (ख) एल॰ जी॰

(ग) रिबॉक (घ) नोकिया

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।

1. वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का .... अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय।
2. व्यापार, पूँजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के माध्यम से .... को बढ़ावा मिलता है।
3. बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वैश्वीकरण की प्रक्रिया में .... भूमिका निभा रही है।
4. विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को .... का कार्य करते हैं।
5. W.T.O. (World Trade Organisation) की स्थापना सन् .... में की गई।

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short- Answer Questions)

1. वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं ?
2. बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं ?
3. विश्व व्यापार संगठन क्या है ? यह कब और क्यों स्थापित किया गया ?
4. भारत में सन् 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं ?
5. उदारीकरण को परिभाषित करें ?
6. निजीकरण से आप क्या समझते हैं ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long- Answer Questions)

1. एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी देश में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के निर्णय पर किन बातों का प्रभाव पड़ता है?
2. वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभावों को बताएँ।
3. भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें।
4. वैश्वीकरण का आम आदमी पर पड़े प्रभावों की चर्चा करें।

परियोजना कार्य (Project Work)

अपने विद्यालय के समीप के किसी गाँव या मुहल्ले के निम्न मध्यम वर्ग के दस लोगों से इन बिंदुओं पर उनकी राय लें और बताएँ कि वैश्वीकरण से उन्हें कितना और कैसे लाभ हुआ है ?

(क) विगत् वर्षों में उनके द्वारा उपभोग की गई वस्तु की संख्या में वृद्धि हुई है अथवा नहीं?

(ख) यदि उनके द्वारा उपभोग की वस्तुओं में वृद्धि हुई है तो क्या– (i) वे वस्तुएँ स्थानीय बाजार की निर्मित है या बड़ी कंपनियों द्वारा (ii) उनके उपभोग की सामग्रियों में कितनी बहुराष्ट्रीय कंपनी का उत्पाद है । (iii) वैश्वीकरण को सरल शब्दों में बताकर उनसे पूछे कि उन्हें इससे लाभ हुआ है अथवा नहीं ।

इन प्रश्नावली के आधार पर दस पंक्तियों में यह बताएँ कि वैश्वीकरण का आम लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ा है अच्छा अथवा बुरा ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर

I.	1. (घ)	2. (ग)	3. (घ)	4. (ख)	5. (क)
II.	1. विश्व	2. वैश्वीकरण	3. मुख्य	4. जोड़ने	5. 1995

*